

1. Indemnity contract is defined under/सतिपूर्ति अनुबंध निम्नलिखित में किसके तहत परिभाषित किया गया है
- Section 124 of the Indian Contract Act/भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124
 - Section 67 of the Indian Contract Act/भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 67
 - Section 127 of the Indian Contract Act/भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 127
 - Section 128 of the Indian Contract Act/भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128
2. Peek Vs Gurney is a famous case related to/पीक बनाम गुर्नी किस स्वदेशी के संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है
- Coercion/जबरदस्ती
 - Fraud/धोखाधड़ी
 - Mistake of fact/तथ्य की गलती
 - Mistake of law/कानून की गलती
3. The Supreme Court invoked the principle of 'Transformative Constitutionalism' in the case of/सिखेस केस के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट 'परिवर्तनशील संवैधानिकता' को लागू किया?
- Navtej Singh Johar Vs Union of India (2018)/नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018)
 - Suresh Kumar Koushal Vs Naz Foundation (2010)/सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज संस्था (2010)
 - Naz Foundation Vs Government of NCT of Delhi, (2009)/नाज संस्था बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली (2009)
 - Aruna Roy Vs Union of India, (2002)/अरुणा रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2002)
4. The provisions of Indian Penal Code apply also to any offence committed by/भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो
- any citizen of India in any place without and beyond India./भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक
 - any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be./किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जलयान या विमान पर, चाहे वह जहाँ भी हो
 - any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India./भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो

भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता हो

- All of the above/उपरोक्त सभी
5. Under the Patent Act which of the following are not patentable?/पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है?
- a method of agriculture or horticulture/कृषि या बागवानी का तरीका
 - a presentation of information/सूचना की प्रस्तुति
 - topography of integrated circuits/एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति
 - All of the above/उपरोक्त सभी
6. World Intellectual Property Organization (WIPO) has replaced pre-existing/विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है
- GATT/ GATT
 - BIRPI/ BIRPI
 - TPRM/ TPRM
 - PCT/ PCT
7. Anuradha Bhasin Vs Union Of India on 10 January, 2020 relates to a challenge under Article 32 of the Constitution seeking issuance of an appropriate writ/अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी, 2020 का सम्बन्ध संविधान के आर्टिकल 32 से है जिसके लिए रिट (writ) जारी करने की आवश्यकता है
- for setting aside orders of the Government by which all modes of communication including Internet have been shut down in J&K/सरकार के इस आदेश को दरकिनारा करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गयी थी
 - for setting aside orders of the Government by which private property was sought to be acquired in J&K/सरकार के ऐसे आदेशों को दरकिनारा करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में निजी संपत्ति के अधिग्रहण करने की जाग की गई थी
 - for setting aside orders of the Government by which J&K was constituted as a UT/सरकार के उन आदेशों को दरकिनारा करना जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है
 - for setting aside orders of the Government by which Ladakh was separated./सरकार के उन आदेशों को दरकिनारा करना जिसके अंतर्गत लद्दाख को अलग किया गया है
8. Section 66A of the Information Technology Act was struck down under Art. 19(1) (a) read with Article 19 (2) in the case of/किसा केस के सन्दर्भ में सूचना एवं

प्रौद्योगिकी के सेक्शन 56A को आर्टिकल 19(1) (a) और आर्टिकल 19 (2) के अंतर्गत खारिज किया या खत्म किया

- a) Justice K. S. Puttaswamy Vs Union of India/जस्टिस के. एस पुतास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
 - b) Kharak Singh Vs State of U.P./खरक सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश
 - c) Govinda Vs State of M.P./गोविंदा बनाम राज्य मध्य प्रदेश
 - d) Shreye Singhal Vs Union of India/श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
9. Article 145(3) of the Indian Constitution states that The minimum number of Judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be.../अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है, जिसमें संविधान की व्याख्या से सम्बंधित कानूनी प्रश्न है, अथवा अनुच्छेद 143 से सम्बंधित कोई भी सुनवाई
- a) Two/दो
 - b) Three/तीन
 - c) Five/पांच
 - d) Nine/नौ
10. M.C. Mehta Vs Union of India 1986 Shriram food and Fertilisers case relates to/एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 शीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है
- a) Oleum Gas leak/ओलियम गैस का रिसाव
 - b) Ganga water cleaning/गंगा जल की सफाई
 - c) Child labour/बाल श्रम
 - d) Bonded labour/बंधुआ मजदूर
11. A. K. Kraipak Vs Union of India relates to/ए.के. कृपाक बनाम भारत संघ संबंधित है
- a) Likelihood of Bias/पूर्वग्रह की संभावना
 - b) Delegated Legislation/प्रत्याभोजित विधान
 - c) Administrative Discretion/प्रशासनिक विवेक
 - d) Notice/नोटिस
12. Judicial control of Delegated Legislation may be exercised on the ground of/प्रत्याभोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है
- a) Doctrine of Ultra vires/अधिकारहीन का सिद्धांत
 - b) Malafides/मालाफाइड्स

- c) Exclusion of Judicial Review/न्यायिक समीक्षा का वहीनकरण
 - d) All of the above/उपरोक्त सभी
13. On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, conferring on daughter coparcenary status by substituting new section for/मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की शुरुआत से, नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करके बेटों की सहभागिता की स्थिति पर सर्वाधिक धारा के अंतर्गत हुई:
- a) Section 6/ धारा 6
 - b) section 10/ धारा 10
 - c) Section 11/ धारा 11
 - d) Section 13/ धारा 13
14. Section 5 of Hindu Marriage Act relates to/हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है:
- a) Void marriages/अमान्य विवाह
 - b) Voidable marriages/अमान्य विवाह (कई सारे)
 - c) Ceremonies of Hindu marriage/हिंदू विवाह के समारोह
 - d) Conditions of Hindu marriage/हिंदू विवाह की शर्तें
15. A marriage between a girl of 22 years marries her maternal uncle's son of 23 years in accordance with the Special Marriage Act. Such marriage is/विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह
- a) Valid/मान्य होगा
 - b) Voidable/अमान्य होगा
 - c) Void/व्यर्थ होगा
 - d) Valid only in north India/सिर्फ उत्तर भारत में मान्य होगा
16. The principle of Res judicata is dealt under Section -- of CPC/पूरन्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा --- के तहत निपटा है
- a) 9/9
 - b) 10/10
 - c) 11/11
 - d) 12/12
17. Section 14 of the C.P.C. deals with/C.P.C. की धारा 14 के तहत निपटा है
- a) Presumption as to decisions of tribunals/अधिकरणों के निर्णयों के रूप में अनुमान
 - b) Presumption as to foreign judgments/विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान

- c) Presumption as to judgments of the lower court/निचली अदालत के निर्णय के रूप में अनुमान
- d) Presumption as to judgments of High Court/उच्च न्यायालय के निर्णय के रूप में अनुमान
18. A, residing in Delhi, publishes in Kolkata statements defamatory of B. B may sue A/A, दिल्ली का रहने वाला है और B से सम्बन्धित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। B, A के ऊपर मुकदमा कर सकता है
- a) Only in Delhi/केवल दिल्ली में
- b) Only in Kolkata/केवल कोलकाता में
- c) In both the place of Delhi and Kolkata/दिल्ली और कोलकाता दोनों जगहों पर
- d) either in Kolkata or in Delhi /या तो दिल्ली या कोलकाता में
19. Which provision under Criminal procedure Code, 1973 deals with the procedure to be adopted by the Magistrate to record confessions and statements? /आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग जजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है?
- a) Section 162/धारा 162
- b) Section 164/धारा 164
- c) Section 163A/धारा 163A
- d) Section 165/धारा 165
20. Attachment of property of person absconding can be done under Section ---- of Cr.P.C./ फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, की धारा के तहत की जा सकती है
- a) 83/83
- b) 82/82
- c) 85/85
- d) 86/86
21. Magistrate may dispense with personal attendance of accused under Section ---- of Cr.P.C./ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, की धारा ---- के अंतर्गत जजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए दियुक्त कर सकता है-
- a) 201/201
- b) 204/204
- c) 205/205
- d) 200/200
22. Section 265A to 265L, Chapter XXA of the Criminal Procedure Code deals with the concept of /अनुच्छेद 265A से लेकर 265L, दंड प्रक्रिया संहिता, अध्याय XXIA का सम्बन्ध किस धारणा से है
- a) Unlawful Assembly/बैरकानूनी तरीके से जमा होना
- b) Arrest without warrant/बिना वारंट के गिरफ्तारी
- c) search and seizures/खोज और बरजटगी
- d) Plea bargaining/दौलत और सौदेबाजी
23. Security for good behaviour from habitual offenders is dealt under/आदतन अपराधी के अच्छे बर्तानों की सुरक्षा किससे सम्बन्धित है:
- a) Section 109 of Cr.P.C./दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 109
- b) Section 110 of Cr.P.C./दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 110
- c) Section 111 of Cr.P.C./दंड प्रक्रिया संहिता का अनुभाग 111
- d) None of the above/उपरोक कोई नहीं
24. Section 105 (b) of Cr.P.C deals/अनुभाग 105(a) का सम्बन्ध निम्नलिखित में से किससे है
- a) Forfeiture of property in certain cases /कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना
- b) Notice of forfeiture of property/संपत्ति को जब्त करने की सूचना
- c) Management of properties seized or forfeited/जब्त या जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन
- d) Identifying unlawfully acquired property/अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना
25. Bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation -- is dealt under/किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो लोकधाम लगायी जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौनसी धारा के अंतर्गत निपटा जाता है:
- a) Section 178 of Cr. P.C./आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 178
- b) Section 469 of Cr. P.C./आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 469
- c) Section 478 of Cr. P.C./आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 478
- d) Section 168 of Cr. P.C./आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 168
26. "decree-holder" means/"डिक्री धारक" का अर्थ है
- a) any person in whose favour a decree has been passed or an order capable of execution has been made/कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है
- b) any person in whose favour a decree has been passed or an order incapable of execution has been made/कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री

परित की गई है या तिष्पादन के लिए अक्षम आदेश दिया गया है।

- ✓ any Citizen in whose favour a decree has been passed or an order capable of execution has been made/कोई भी नागरिक जिसके पक्ष में एक डिक्री परित की गई है या तिष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है।
- ✓ any corporation in whose favour a decree has been passed or an order capable of execution has been made/कोई भी निगम जिसके पक्ष में एक डिक्री परित की गई हो या तिष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया हो।
27. Voluntarily throwing or attempting to throw acid is an offence punishable under/स्वैच्छया से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है-
- Section 326 B of the Indian Penal Code/भारतीय दंड संहिता की धारा 326 B
 - Section 120 B of the Indian Penal Code/भारतीय दंड संहिता की धारा 120 B
 - Section 509 of the Indian Penal Code/भारतीय दंड संहिता की धारा 509
 - Section 295B of the Indian Penal Code/भारतीय दंड संहिता की धारा 295 B
28. A is at work with a hatchet; the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is/ "A" कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उड़कर उड़ती हुई नजदीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ "A" के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह "A" के द्वारा किया गया-
- An Offence of murder/हत्या का अपराध माना जायेगा।
 - An offence of Culpable homicide/गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जायेगा।
 - Not an offence/अपराध नहीं माना जायेगा।
 - An Offence of causing grievous hurt/सभीर घोट पहुँचाने का अपराध माना जायेगा।
29. A, with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy, writes a letter in imitation of Z's handwriting, purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy, and puts the letter in a place which he knows that the officers of the police are likely to search - A has committed an Offence under/ A, Z को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से, Z को तिष्पावट की लपन में एक आपराधिक पत्र के रूप में इस तरह के एक साथी को

संबोधित करते हुए, एक पत्र लिखता है, और इस पत्र A ऐसी जगह पर रखता है, जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है - A ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है।

- Section 256 of IPC/IPC की धारा 256 के अंतर्गत
 - Section 192 of IPC/IPC की धारा 192 के अंतर्गत
 - Section 195 A of IPC/IPC की धारा 195 A के अंतर्गत
 - Section 201 of IPC/IPC की धारा 201 के अंतर्गत
30. Under Section 70 of the Indian Contract Act, where a person lawfully does anything for another person, or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of, or to restore, the thing so done or delivered. This principle is known as/भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है, या उसे कुछ भी देता है, तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है, और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके विषय में एक काम के लिए मुआजजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं-
- A Contract of Uberimae fide/उबेरिमा फाइडस कॉन्ट्रैक्ट
 - Implied Agency/इम्प्लाइड एजेंसी
 - Quantum meruit/क्वांटम मेरिट
 - De nova contract/दो नोवा कॉन्ट्रैक्ट
31. Agreement is/समझौता क्या है?
- a promise or set of promises forming consideration to each other/एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे
 - enforceable by law/कानून द्वारा लागू करने योग्य
 - enforceable contract/लागू करने योग्य अनुबंध
 - Un enforceable by law/कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं
32. Under the Land Acquisition Act, the expression "land" includes/भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, उद्धारण "भूमि" में सम्मिलित है
- benefits to arise out of land/भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ
 - things attached to the earth/पृथ्वी से जुड़ी चीजें
 - things permanently fastened to anything attached to the earth/चीजें जो स्थायी रूप से पृथ्वी किन्हीं भी चीजों से जुड़ी हैं जो की पृथ्वी से जुड़ी हैं
 - All of the above/उपरोक्त सभी

33. Temporary occupation of waste or arable land, procedure when difference as to compensation exists is provided under/विनाश या कृषि क्षेत्र भूमि पर अस्थायी कब्जा, प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है।
- ✓ a) Section 32 of Land Acquisition Act/भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 32
- b) Section 30 of Land Acquisition Act/भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30
- c) Section 35 of Land Acquisition Act/भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35
- d) Section 31 of Land Acquisition Act/भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 31
34. X, Y, Z jointly promise to pay A an amount of Rs. 50,000/- Subsequently X, Y became untraceable. Can A compel Z to pay? / X, Y, Z संयुक्त रूप से 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में X, Y अप्राप्य हो जाते हैं। क्या A भुगतान करने के लिए Z को मजबूर कर सकता है।
- a) A can, under Section 43 para 1/A, धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है।
- b) A can under Section 49 para 1/A, धारा 49 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है।
- c) A cannot and will have to wait till X, Y become traceable/A ऐसा नहीं कर सकता, X और Y के मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा।
- ✓ d) Z can be compelled only for one third/Z को केवल एक तिहाई के लिए मजबूर किया जा सकता है।
35. Delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. This process is termed as/एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को आन की डिलीवरी, जो कि उद्देश्य पूरा होने पर, उन्हें बिलिखित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाना या निपटारा जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है।
- a) Agency/एजेंसी
- b) Bailment/जमानत
- ✓ c) Guarantee/गारंटी
- d) Contingency/आकस्मिकता
36. Section 14A inserted by the THE SPECIFIC RELIEF (AMENDMENT) ACT, 2018, relates to/ विशिष्ट राहतयता (AMENDMENT) अधिनियम, 2018 के प्राधान्य से की गयी धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है।
- a) Power of the Courts to engage experts/विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार
- b) Establishment of Special Court/विशेष न्यायालय की स्थापना
- c) Expeditious disposal of case/मामले का शीघ्र निपटारा
- d) Specific performance with regard to contracts/अनुबंध के संबंध में विशिष्ट अनुपालन
37. In which of the following case the offence of sedition was in issue/विम्बलखित है से कौनसा मामला राजद्रोह से सम्बंधित है:
- a) Queen Empress Vs Bal Gangadhar Tilak/कौतिल बनारस बाल गंगाधर तिलक
- b) Niharendu Dutt Mazumdar Vs Emperor/निहारेन्दु दत्त मजूमदार बनाम एमपरेर
- ✓ c) Keedar Nath Singh Vs State of Bihar/केदार नाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार
- d) All of the above/उपरोक्त सभी
38. Deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs. - is an offence under/अपमानपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपमान धर्म का अपमानजनक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को लाराज करना है - निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है।
- ✓ a) Section 295/धारा 295
- b) Section 295A/धारा 295A
- c) Section 265A/धारा 265A
- d) Section 276/धारा 276
39. Under Section 29 of Cr.P.C. The Court of a Chief Judicial Magistrate may pass any sentence authorized by law except/आपराधिक प्रक्रिया संहिता, की धारा 29 के अंतर्गत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत यानुसार द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को फारित कर सकती है, शिवाय -
- a) A sentence of death/मौत की सजा
- b) Imprisonment for life/आजीवन कारावास
- c) Imprisonment for a term exceeding seven years/सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास
- ✓ d) All of the above/उपरोक्त सभी
40. Provision regarding filing of suits by an alien under the Code of Civil procedure is dealt under/सांख्यिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दाखल करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है।
- a) Section 21A/धारा 21A

- b) Section 15, धारा 15
 c) Section 218, धारा 218
 d) Section 83, धारा 83
41. An order issued by court under Civil Procedure Code 1908 as per order XXX, rule 46, for recovery of amount due to judgment creditor - is known as/आवधिक प्रक्रिया संहिता 1908, के नियम 46 के आदेश XX के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक परमाज्ञ जारी किया जाता है जिसमें निर्णय लेनदार को बकाया राशि की वसूली को कहते हैं।
 a) IT Order/आईटी आदेश
 b) Garnishee Order/गर्नीशी आदेश
 c) Decree Holder order/डिक्री होल्डर का आदेश
 d) Bank Order/बैंक का आदेश
42. Section 88 read with Order XXXV of the Code of Civil Procedure, 1908 deals with/सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXV की धारा 88, 1908 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
 a) Interpleader suit/अंतर्बोधीय मुकदमा
 b) Interlocutory Order/अंतर्बोधीय आदेश
 c) Restitution Order/पुनर्स्थापन आदेश
 d) Attachment Order/अनुबन्धन आदेश
43. The national consumer dispute redressal commission was constituted in the year/राष्ट्रीय उपभोक्ता अध्याय निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था।
 a) 1988/1988
 b) 1998/1998
 c) 1999/1999
 d) 1997/1997
44. What is the limitation period applicable to the three forums in entertaining a complaint under The Consumer Protection Act, 1986/उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ल करने में तिनो मंचो पर लागू सीमा की अवधि क्या है।
 a) 3 years from the date on which the cause of action has arisen/उस तारीख से 3 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है।
 b) 5 years from the date on which the cause of action has arisen/उस तारीख से 5 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है।
 c) 4 years from the date on which the cause of action has arisen/उस तारीख से 4 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है।
 d) 2 years from the date on which the cause of action has arisen/उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है।
45. "Mere illegality of the strike does not per se spell unjustifiability" - Justice Krishna Iyer. Name the case./हड़ताल की मात्र अवैधता पर अपन अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। जस्टिस कृष्णा इयर, केस का नाम क्या है।
 a) Chandermahal Estate Vs Its workmen/चंद्रमहाल ईस्टेट बनाम उसके कार्यकर्ता
 b) Associated Cement Ltd., Vs Their workmen/एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड उनसे काम करने वाले
 c) Gujarat Steel Tubes Vs Gujarat Steel Tubes Mazdoor Sabha/गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर संघ
 d) Indian General Navigation of Railway Co. Ltd., Vs Their workmen/इंडियन जेनरल नैवीगेशन, बनाम उससे काम करने वाले
46. A workman aggrieved by the order of may directly make an application to the labour court or tribunal for adjudication of the dispute and the court/tribunal is empowered to adjudicate such dispute as it had been referred to it by the appropriate government/एक कार्यकर्ता के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के समान के सिविल न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय / न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है।
 a) Dismissal, discharge and retrenchment/बर्खास्तगी, निर्वहन और छुट्टी
 b) Dismissal, discharge, retrenchment or otherwise termination of service/बर्खास्तगी, निर्वहन, छुट्टी या अन्यथा सेवा की समाप्ति
 c) Discharge simpliciter exclusively/साधारण रूप से छुट्टी करना
 d) Dismissal and retrenchment exclusively/विशेष रूप से बर्खास्त करना और छुट्टी
47. Vis major means/दिव्यत को मतलब है।
 a) Act of God/भगवान द्वारा किया गया कार्य
 b) Act of individual/अनुपुन्य द्वारा किया गया कार्य
 c) Act of other party/अन्य पक्ष द्वारा किया गया कार्य
 d) Act of plaintiff/अभियोगी द्वारा किया गया कार्य
48. According to Classical doctrine of Act of State in law of Torts means/टॉर्स के क्लासिकल में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है।
 a) an act of the sovereign power of a country, that cannot be challenged, controlled or interfered

with by municipal courts/किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम, जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है

- b) an act of the Judiciary of a country, that cannot be challenged, controlled or interfered with by municipal courts/किसी देश की न्यायपालिका का एक कार्य, जिसे नगर प्रशासन न्यायालयों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है
- c) an act of the sovereign power of a country, that can be challenged, controlled or interfered with by municipal courts/किसी देश की संप्रभु सत्ता का एक अधिनियम, जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप किया जा सकता है

✓ d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

49. In Torts, all persons who aid, or counsel, or direct or join in the commission of a wrongful act, are known as/टॉट्स में, सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य के करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है

- a) Abettors/उसकातेवाला
- b) Joint tortfeasors/जॉइंट टॉट फीजर्स
- c) Tort holders/टॉट होल्डर्स
- ✓ d) Tort holders in common/टॉट होल्डर्स इन कॉमन

50. A is accused of waging war against the Government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant, as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. - under which section of the India Evidence Act. /A पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है, और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेनदेन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, इसलिए A उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है - ऐसी स्थिति भारत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है

- ✓ a) Section 12/धारा 12
- b) Section 6/धारा 6
- c) Section 3/धारा 3
- d) Section 5/धारा 5

51. Section 110 of the Evidence Act deals with/साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है

- a) Documentary Evidence/दस्तावेजी साक्ष्य
- b) Exclusion of Oral Evidence/मौखिक साक्ष्य का बहिष्करण

- ✓ c) Burden of proof as to ownership/स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ
- d) Proof of guilt./अपराध का प्रमाण

52. Section 113 (A) of the Evidence Act deals with/साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A किससे संबंधित है

- a) Presumption as to abetment of murder/हत्या करने के इरादे का तीव्रता का अनुमान
- b) Presumption as to rape and abetment of suicide by a woman/किसी लड़की के बलात्कार और उसकी हत्या के इरादे का अनुमान
- c) Presumption as to abetment of kidnap of a girl/एक लड़की के अपहरण की धमकी देने का अनुमान
- ✓ d) Presumption as to abetment of suicide by a married woman/एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान

53. The Supreme Court has legalised living wills and passive euthanasia subject to certain conditions in the case of/सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छासमूच्य को वैध कर दिया है

- a) Aruna Ramachandra Shanbaug Vs Union of India (2011)/अरुणा रामचंद्र शांभावग बनाम भारत संघ (2011)
- b) Common Cause Vs Union of India, (2018) 5 SCC 1./कॉमन कॉस बनाम भारत संघ, (2018) 5 SCC 1.
- ✓ c) Gian Kaur Vs State of Punjab (1996)/गिमान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)
- d) D Chenna Jagadeeswar Vs State of A.P. (1988)/डी चेंना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1988)

54. Article 310 of the Constitution mentions about/संविधान की अनुच्छेद 310 इसके बारे में संबंधित है

- a) Doctrine of Immunities and Instrumentalities with reference to civil servants/सिविल सेवकों के संदर्भ में अतन्त्रताओं और उपकरणों का सिद्धांत
- b) Doctrine of legitimate expectation with reference to civil servants/सिविल सेवकों के संदर्भ में वैध अपेक्षा का सिद्धांत
- ✓ c) Doctrine of natural justice with reference to civil servants/सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
- d) Doctrine of pleasure with reference to civil servants/सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत

55. Right to know the antecedents of the candidates in the election flow from/चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार

- a) Article 19 (1)(a)/अनुच्छेद 19 (1)(a)

- b) Article 20/अनुच्छेद 20
 ✓ c) Article 13/अनुच्छेद 13
 d) Article 14/अनुच्छेद 14
56. In the Preamble of the Indian Constitution, the expression "liberty" is followed by the words/ भारतीय संविधान के प्रस्तावना में "स्वतंत्रता" की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौनसे शब्द आते हैं
- a) Of status and opportunity/स्थिति और अवसर की
 b) Of thought, expression, belief, faith and worship/विचारधारा, अभिव्यक्ति, धरना, आस्था और पूजा की
 ✓ c) Assuring the dignity of the individual/व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना
 d) Justice, social economic and political/न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक
57. The Plea Bargaining is applicable only in respect of those offences for which punishment of imprisonment is up to a period of/"Plea Bargaining" केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि वर्ष तक है:
- a) 7 years / 7 वर्ष
 b) 10 years/10 वर्ष
 c) 11 years/11 वर्ष
 ✓ d) 14 years/14 वर्ष
58. "From a plain reading of Section 195 Cr.P.C. it is manifest that it comes into operation at the stage when the Court intends to take cognizance of an offence under Section 190(1) Cr.P.C. and it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an F.I.R. which discloses a cognisable offence.... In other words, the statutory power of the Police to investigate under the Code is not in any way controlled or circumscribed by Section 195 Cr.P.C." - This was held by the Supreme Court in the case of/सीआरपीसी की धारा 195 को अगर आसानी शब्दों में समझा जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस सजाय से आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 190 (1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है. दूसरे शब्दों में, संज्ञित के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है. - ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा
- a) Nalini Vs State of Tamilnadu/नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य
 b) ✓ Raj Singh Vs State [(1998)]/राज सिंह बनाम राज्य [(1998)]
 c) Shamsher Singh Vs State of Punjab/शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य
 d) State of Himachal Pradesh Vs Tara Dutta/राज्य हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दुता
59. The question is, whether A owes B rupees 10,000. Which of the following statements are relevant under Evidence Act/सवाल यह है कि क्या A, B को 10,000 रुपये का देयदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है?
- a) The facts that A asked C to lend him money, /वह लख्ये जहाँ A ने C को देते उपर देने के लिए कहा
 b) D said to C in A's presence and hearing - "I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees." /D बो को उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा "मैं आपको यह धर भरोसा नहीं करने को सलाह देता हूँ, क्योंकि उसके पास वो ज 10,000 रुपये का बकाया है."
 c) A went away without making any answer/जिसे कोई जवाब दिए चला गया
 ✓ d) All of the above/उपरोक्त सभी
60. So much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered by the police may be proved under/इस तरह की बहुत सारी जानकारी, चाहे यह अनुसन्धान के प्रतिपादित करती हो या नहीं, जो कि पुलिस द्वारा खोजी गए तथ्य से अलग हो, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है
- a) Section 25 of the Evidence Act/साक्ष्य अधिनियम की धारा 25
 b) Section 26 of the Evidence Act/साक्ष्य अधिनियम की धारा 26
 c) Section 27 of the Evidence Act/साक्ष्य अधिनियम की धारा 27
 ✓ d) Section 29 of the Evidence Act/साक्ष्य अधिनियम की धारा 29
61. When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science, or art, or as to identity of handwriting, or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in questions as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts. - This is under _____ of the Evidence Act/जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान, या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि, या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है, तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल हैं, को प्रासंगिक तथ्य

माना जाएगा। - यह तथ्य साब्य अधिनियम के धारा ----
- अंतर्गत आता है:

- a) Section 42/धारा 42
 b) Section 45/धारा 45
 c) Section 50/धारा 50
 d) Section 55/धारा 55
62. A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A, and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that, at the time of the sale, he had no title. He will not be allowed to prove his want of title. - Which Section of the Evidence Act is applicable? / A जानबूझकर और झूठ बोलकर B को ये विश्वास दिलाने है की जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह B को यह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है, बाद में जमीन A की संपत्ति बन जाती है और A यह कहकर बिक्री रोक देता है की बेवजह के समय, वो जमीन उसकी नहीं थी, उसे अपने इस भालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी - साब्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू है?
- a) Section 92/धारा 92
 b) Section 124/धारा 124
 c) Section 115/धारा 115
 d) Section 101/धारा 101
63. The Arbitration Act 1996 repeals/मर्यादस्थ अधिनियम 1996 निरस्त करता है:
- a) The Arbitration Act, 1940, मध्यस्थता अधिनियम, 1940
 b) The Arbitration (Protocol and Convention) Act, 1937/मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937
 c) the Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act, 1961, /विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961
 d) All of the above/उपरोक सभी
64. Parliament may by law establish Administrative Tribunals under ----- of the Constitution/संसद संविधान के के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है:
- a) Article 323B/अनुच्छेद 323B
 b) Article 323A/अनुच्छेद 323A
 c) Article 239/अनुच्छेद 239
 d) Article 323/अनुच्छेद 323
65. The Bar Council of India has to lay down the standards of professional conduct and etiquette for the Advocates under/बार काउंसिल ऑफ इंडिया

अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है

- a) Section 3 of the Advocate Act, 1961/अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3
 b) Section 7 (1) (b) of the Advocate Act, 1961/अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 7 (1) (बी)
 c) Section 17 of the Advocate Act, 1961/अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17
 d) Section 18 of the Advocate Act, 1961/अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 18
66. According to Sec. 49 of the Advocate Act of 1961 the Bar Council of India has power to make rules/अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो
- a) qualifications for membership of a Bar Council and the disqualifications for such membership/बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता
 b) the class or category of persons entitled to be enrolled as advocates/अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी
 c) the standards of legal education to be observed by universities in India and the inspection of universities for that purpose. /भारत में विधि विद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विधि विद्यालयों के निरीक्षण के लिए
 d) All of the above/उपरोक सभी
67. India, that is Bharat, shall be a/इंडिया, जो कि भारत है, एक -
- a) Federation of States/संघीय राष्ट्र है
 b) quasi federal/व्यापारी संघीय राष्ट्र है
 c) Union of states/राज्यों का संघ है
 d) Unitary state of a special type/एक विशेष प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है
68. In M. C. Mehta Vs. Union of India, AIR 1987 SC1086 (Sri Ram Fertilizers case) the court held that/श्री एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, AIR 1987 SC1086 (श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे) में अदालत ने यह फैसला किया कि
- a) in escape of toxic gas the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vis-a-vis the tortious principle of strict liability./उपरोक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है, जो

जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की देनदारीएँ किसी भी अपवाद के अधीन नहीं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती हैं।

- b) In escape of a dangerous animal the owner is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vis-a-vis the tortious principle of strict liability./ खतरनाक जानवर का गतिविधि उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो इस खतरनाक जानवर के छूटने की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की देनदारी, जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती है, किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है।

✓ In escape of toxic gas, the enterprise is strictly liable to compensate all those who are affected by the accident and such liability is subject to any of the exceptions which operate vis-a-vis the tortious principle of strict liability/उद्योगिक उम सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है, जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। और इस तरह की देनदारी, इन सभी अपवादों के अधीन है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती हैं।

- d) A company or a corporation is not a state and hence not liable for leak of toxic gas affecting the health of the people/एक कंपनी या निगम एक राज्य या राष्ट्र नहीं है और इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जहरीली गैस के रिसाव के लिए उत्तरदायी नहीं है।

69. According to Environmental Protection Act, 1986, 'environmental pollutant' means, 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है

- a) any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be, or tend to be, helpful to environment/किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ से मौजूद ऐसी-मिलावट / संकेदण, जो पर्यावरण के लिए सहायक हो या हो सकता हो
- b) only gaseous substance present in such concentration as may be, or tend to be, injurious to environment/इस तरह के मिलावट / संकेदण से मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो की पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो
- c) any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be, or tend to be,

injurious to environment/किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ से मौजूद ऐसी-मिलावट / संकेदण, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो

- d) any solid, liquid present in such concentration as may be, or tend to be, injurious to environment/किसी भी ठोस या तरल पदार्थ से मौजूद ऐसी-मिलावट / संकेदण, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो

70. National Green Tribunal cannot exercise its Jurisdiction with reference to/राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता

- a) Wildlife (Protection) Act, 1972/वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- b) Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006/शेड्युल्ड ट्राइब्स एंड ओर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स (वन राइट्स की मान्यता) अधिनियम, 2006
- ✓ c) The Public Liability Insurance Act, 1991/सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
- d) both A & B/दोनों A & B

71. An attempt to acquire sensitive information such as usernames, passwords, and credit card details (and sometimes, indirectly, money) by masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication – is known as/इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक अरोसेमेट इवेंट के रूप में पहचान करने उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण (और कभी-कभी, अप्रत्यक्ष रूप से, धन) के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को - के रूप में जाना जाता है -

- a) Phishing/इंटरनेट धोखाधड़ी
- b) Smishing/संदेश भेजकर धोखाधड़ी
- c) Phishing/धोखा या कपला
- ✓ d) Diding/इलेक्ट्रॉनिक लेन भेजकर धोखाधड़ी

72. Under Section 82 of the Indian Penal Code, nothing is an offence which is done by a child under the age of 12/इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा किये गये जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता

- a) 14 years/14 साल
- ✓ b) 7 years/07 साल
- c) 18 years/18 साल
- d) 21 years/21 साल

73. R. V. Dudley & Stephen stands for the principle that/आर वी डडली और स्टेफेन किस सिद्धांत के समर्थक हैं:

- a) Killing an innocent life to save his own is not a defence and necessity cannot be pleaded as a defence against murder/अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान तथा आवश्यक नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए
- b) Necessity can be pleaded as a defence against murder, killing an innocent life to save his own may become inevitable/जबरन पड़ने पर हत्या के खिलाफ बचाव के रूप में निवेदन किया जा सकता है, अपने स्वयं को बचाने के लिए एक निर्दोष के जीवन को खत्म करना जरूरी हो सकता है
- c) Killing out of mercy is a defence and necessity cannot be pleaded as a defence against murder./बिना दया के किसी की हत्या करना बचाव नहीं है और ना ही जरूरी है और अपने बचाव के लिए इसकी दलील नहीं दी जा सकती
- d) None of the above/उपरोक्त कोई भी नहीं
74. The utility of Public Interest Litigation/जनहित याचिका की उपयोगिता है
- a) Liberalised locus standi/उदारीकृत लोकस स्टैंडी
- b) The proceedings are Non-Adversarial/गैर प्रतिद्वन्द्वित कार्यवाही
- c) Procedural requirements are liberalized/प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना
- र्थ) All of the above/उपरोक्त सभी
75. The petitioner, a professor of political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provisions, challenged the practice followed by the state of Bihar in re-promulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner as a member of public has 'sufficient interest' to maintain a petition under Article 32 - This relates to the case of/याचिकाकर्ता, राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर, जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संबंध है। यह मामला संबंधित है
- a) *Parmahand Katara Vs Union of India - AIR 1989, SC 2039/परमानंद कटारा बनाम युनियन ऑफ इंडिया - AIR 1989, SC 2039*
- b) *D.C. Wadhwa Vs State of Bihar, AIR 1987 SC 579/डी. सी. वधवा बनाम बिहार राज्य, AIR 1987 SC 579*
- c) *Neeraja Choudhary Vs State of Madhya Pradesh AIR 1984SC1099/नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश AIR 1984SC1099*
- d) *Chameli Singh Vs State of U.P. AIR 1996, SC1051/चमेली सिंह बनाम यू.पी. AIR 1996, SC1051*
76. Where a legal wrong or a legal injury is caused to a person or to a determinate class of persons by reason of violation of any constitutional or legal right or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision or without authority of law or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened and such person or determinate class of persons by reasons of poverty, helplessness or disability or socially or economically disadvantaged position unable to approach the court for relief, any member of public can maintain an application for an appropriate direction, order or writ in the High Court under Article 226 and in case any breach of fundamental rights of such persons or determinate class of persons, in this court under Article 32 seeking judicial redress for the legal wrong or legal injury caused to such person or determinate class of persons." - Justice Binagwani in the case of/ "जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के विना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को धारण है और ऐसे व्यक्ति या शारीरी, असहयता या विकासगत या सामाजिक या आर्थिक रूप से दयित लोगों के घने को निर्धारित करते हैं जो राहत के लिए अदालत को दरवाजा खटखट सकते हैं, जबकि के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा, आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के घने का निर्धारण करने के मामले में, अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। - जस्टिस बिनग्वानी ने ऐसा किस मामले में कहा
- a) *Peoples Union for Democratic Rights Vs Union of India/पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ*
- b) *Ashok Kumar Pandey Vs State of West Bengal/अशोक कुमार पांडे बनाम बंगाल* सी। के राज्य

- c) S. P. Gupta Vs Union of India/एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ
 d) Janata Dal Vs H. S. Chowdhary/जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी
77. Imposition of compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences is dealt under/झूठे या धिंकीले दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटारा जाता है।
 a) Section 33 of CPC/सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33 में
 b) Section 35A of CPC /सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35A
 c) Section 30 of CPC /सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 30
 d) Section 35 of CPC /सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35
78. Which provision under the Code of Civil Procedure deals with substituted service of summons upon the defendant/नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समतल की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है।
 a) - O.S R.19A/O.S R.19A
 b) O.S R.19/O.S R.19
 c) O.S R.20/O.S R.20
 d) O.S R.21/O.S R.21
79. Among other things, the Function of Bar council of India includes laying down standards of professional conduct and etiquette for advocates. - Under which section of the Advocates Act/अन्य बातों के अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए शैक्षिक आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं - ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है।
 a) Section 7/धारा 7
 b) Section 8/धारा 8
 c) Section 9/धारा 9
 d) Section 6/धारा 6
80. According to Justice 'Abbot Parry' what are the "Seven Lamps of Advocacy". /न्यायमूर्ति अबॉट पैरी 'के अनुसार,' बरकत के सात दीपक क्या हैं।
 a) (i) Honesty (ii) Courage (iii) professionalism (iv) Wit (v) Eloquence. (vi) Judgment and (vii) Fellowship. / (i) ईमानदारी (ii) साहस (iii) व्यावसायिकता (iv) बुद्धि (v) वाग्मिता, (vi) निर्णय और (vii) अध्येतावृत्ति
 b) (i) Honesty (ii) Courage (iii) Industry (iv) Wit (v) Eloquence. (vi) Judgment and (vii) Fellowship. / (i) ईमानदारी (ii) साहस (iii) उद्योग (iv) बुद्धि (v) वाग्मिता, (vi) निर्णय और (vii) अध्येतावृत्ति
 c) (i) influence (ii) Courage (iii) Industry (iv) Wit (v) Eloquence. (vi) Judgment and (vii) Fellowship. / (i) प्रभाव (ii) साहस (iii) उद्योग (iv) बुद्धि (v) वाग्मिता, (vi) निर्णय और (vii) अध्येतावृत्ति
81. Minimum number of Directors in a Public company/एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है।
 a) 3/3
 b) 10/10
 c) 12/12
 d) 5/5
82. An associate company, in relation to another company, means/एक सहयोगी कंपनी, किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है।
 a) a company in which that other company has a significant influence, but which is a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company/एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो कंपनी का एक सहायक कंपनी है, जिसमें ऐसा प्रभाव होता है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल होती है।
 b) a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company/एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है।
 c) a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and does not include a joint venture company/एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त कंपनी शामिल नहीं है।
 d) a company in which that other company has full shares, and is a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company/एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी के पूरे शेयर हैं, और इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की एक सहायक कंपनी है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है।

83. Section 66A of Information Technology Act was held unconstitutional in the case of/सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था।
- Justice K. S. Putta swamy Vs Union of India/जस्टिस के एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ
 - M P Sharma Vs Satish Chandra/एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र
 - Shreye Singhal Vs Union of India/श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
 - Gagan Harsh Sharma Vs the State of Maharashtra/गगन हार्श शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य
84. A Teacher is not a workman within the purview of Industrial Disputes Act, held in the case of/एक शिक्षक, औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया।
- The Workmen Vs Greaves Cotton & Co. Ltd. & Ors/वर्कर्स बनाम ग्रीव्स कोटन एंड कंपनी लिमिटेड एवं अन्य
 - John Joseph Khokar Vs Bhadange B. S. & ors/जॉन जोसेफ खोकर बनाम भडंगे बी.एस. एवं अन्य
 - A. Sundarambal Vs Government of Goa/सुंदरामबाल बनाम गोवा सरकार
 - Dinesh Sharma and Ors. Vs State of Bihar/दिनेश शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य
85. According to Factories Act/कारखाना अधिनियम के अनुसार
- "child" means a person who has not completed his fifteenth year of age/"बच्चे" का अर्थ है की एक व्यक्ति जिसने अपनी पंद्रहवीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है।
 - "child" means a person who has not completed his fourteenth year of age/"बच्चे" का अर्थ है की एक व्यक्ति जिसने अपनी चौदहवीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है।
 - "child" means a person who has not completed his eighteenth year of age/"बच्चे" का अर्थ है की एक व्यक्ति जिसने अपनी अठारहवीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है।
 - "child" means a person who has not completed his sixteenth year of age/"बच्चे" का अर्थ है की एक व्यक्ति जिसने अपनी सोलहवीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है।
86. According to Income Tax Act "zero coupon bond" means a bond/आयकर अधिनियम के अनुसार "शून्य कूपन बॉन्ड" का अर्थ एक बॉन्ड है जो की
- issued by any infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or scheduled bank on or after the 1st day of June, 2005, किसी भी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून, 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है;
 - in respect of which no payment and benefit is received or receivable before maturity or redemption from infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or scheduled bank, जिसके संबंध में इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या पुटबैक से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता है।
 - which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf, /जो कि फेड सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
 - of the above/उपरोक्त सभी
87. Provisions relating to GST are inserted in the Constitution by/GST से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गयी है।
- The Constitution (one hundred and first) Act 2016/संविधान (एक सौ एक वा) अधिनियम 2016
 - The Constitution (one hundred and second) Act 2016/संविधान (एक सौ दो वा) अधिनियम 2016
 - The Constitution (eighty fourth) Act 2016/संविधान (अठारहवा) अधिनियम 2016
 - The Constitution (seventy seven) Act 2016/संविधान (सत्तरवा) अधिनियम 2016
88. Suits by indigent persons is dealt under/अप्य व्यक्तिों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके तहत निपटा जाता है।
- Order 44 of C.P.C./सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 44
 - Order 33 of C.P.C./सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 33
 - Order 55 of C.P.C./निविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 55
 - Order 22 of C.P.C./सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 22
89. Res gestae, Relevancy of facts forming part of same transaction is dealt under/Res gestae, समान तैल-देत का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता इसके तहत निपटाया जाता है।

- a) Section 6 of the Evidence Act/साक्ष्य अधिनियम की धारा 6
- b) Section 17 of the Evidence Act/साक्ष्य अधिनियम की धारा 17
- c) Section 18 of the Evidence Act/साक्ष्य अधिनियम की धारा 18
- d) Section 20 of the Evidence Act/साक्ष्य अधिनियम की धारा 20
90. The definition of 'money' under GST law does not include/जीएसटी कानून के तहत "मुद्रा" की परिभाषा में में शामिल नहीं है
- a) Letter of Credit/लेटर ऑफ क्रेडिट
- b) Currency held for numismatic value/मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा
- c) Pay order/ पे ऑर्डर
- d) Traveler cheque/ट्रैवेलर चेक
91. Under Article 279A GST Council is constituted by/अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है
- a) Prime Minister and his Council of Ministers/प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद
- b) Respective Governors of the State/राज्य के सम्मानित राज्यपाल
- c) The President/राष्ट्रपति
- d) A collective body of Union and States/संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय
92. The definition of Contract is defined under/अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गयी है
- a) Section 2(a) of the Indian Contract Act. /भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (a) में
- b) Section 2(h) of the Indian Contract Act. /भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (h) में
- c) Section 2(d) of the Indian Contract Act. /भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (d) में
- d) Section 2(g) of the Indian Contract Act. /भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (g) में
93. The Hindu Succession (Amendment) Act (HSAA) 2005 provides for women./हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम (HSAA) 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है:
- a) coparcenary rights at par with men./पुरुषों के साथ समानता पर अधिकार
- b) inheritance rights in agricultural land from her parents at par with her brothers./अपने माता-पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार
- c) inheritance of the self-acquired agricultural land of her deceased husband./अपने मृत पति की स्व-अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार
- d) All of the above./उपरोक्त सभी
94. Section 25 of the Hindu Marriage Act provides for/हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है
- a) Custody of the Children/बच्चों की हिरासत
- b) Permanent alimony and maintenance/स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव
- c) Maintenance Pendente lite/रखरखाव Pendente lite
- d) Division of matrimonial property/वैवाहिक संपत्ति का विभाजन
95. A Hindu wife had been living with her children and all the children had been brought up by her without any assistance and help from the husband many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under/एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रखरखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी. पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव की हकदार है
- a) Section 18 (2) (f) of Hindu Adoptions and Maintenance Act/हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18 (2) (f)
- b) Section 18 (2) (d) of Hindu Adoptions and Maintenance Act/हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18 (2) (d)
- c) Section 18 (2) (a) of Hindu Adoptions and Maintenance Act/हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18 (2) (a)
- d) Section 18 (2) (e) of Hindu Adoptions and Maintenance Act/हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18 (2) (e)
96. Requisites of a valid adoption: no adoption shall be valid unless- (i) the person adopting has the capacity, and also the right, to take in adoption; (ii) the person giving in adoption has the capacity to do so; (iii) the person adopted is capable of being taken in adoption; and (iv) the adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this Chapter, - mentioned under/एक वैध गोद लेने के अनुरोध: कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक- (i) गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता, और अधिकार भी है; (ii) गोद देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है; (iii) गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है;

और (v) इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गौद लिया गया है। - इसके तहत उल्लेख किया गया है

- a) Section 6 of Hindu Adoptions and Maintenance Act/हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6
- b) Section 8 of Hindu Adoptions and Maintenance Act/हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 8
- c) Section 12 of Hindu Adoptions and Maintenance Act/हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 12
- d) Section 10 of Hindu Adoptions and Maintenance Act/हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 10
97. According to the Muslim women (protection of right son marriage) act, 2019, any pronouncement of talaq as defined under the Act by a Muslim husband upon his wife, by words, either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever, shall be/ the Muslim women (protection of right son marriage) act, 2019 के अनुसार, मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तालाक का उच्चारण, शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो
- a) Void/उसका कोई मतलब नहीं है
- b) Cognizable/हस्तक्षेप योग्य होगा
- c) compoundable/संयोजनीय
- d) All of the above/उपरोक्त सभी
98. The UNCITRAL Model Law and Rules do not become part of the Arbitration Act so as to become an aid to construe the provisions of the Act. - held in the case of/UNCITRAL मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके। ऐसा इस मामले में माना गया
- a) Union of India Vs East Coast Boat Builders and Engineers Ltd. /यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
- b) Union of India Vs M.C. Mehta, /यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम.सी. मेहता
- c) Tata Press Ltd Vs Union of India/टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ
- d) Union of India Vs Indian Change Chrome Ltd./यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडियन चेंज क्रोम लिमिटेड
99. According to Section 7(4) of the Arbitration and Conciliation Act, an arbitration agreement is in writing if it is contained in—/मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार, ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता संगति माना जायेगा यदि वह लिखित में

- a) a document signed by the parties./घाटियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है
- b) an exchange of letters, telex, telegrams or other means of telecommunication which provide a record of the agreement./इलेक्ट्रॉनिक साधन से संचार सहित पत्र, टेलीक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जो संगठित का अभिलेख प्रस्तुत करता है
- c) an exchange of statements of claim and defence in which the existence of the agreement is alleged by one party and not denied by the other./दावे और बचाव के बयानों का एक आदान-प्रदान जिसमें संगठित का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।
- d) All of the above/इनमें से कोई भी
100. Waiver of right to object deviance from arbitration agreement is mentioned under _____ of the Arbitration and Conciliation Act./मध्यस्थता संगठितों से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और मुहल अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है:
- a) Section 7/धारा 7
- b) Section 4/धारा 4
- c) Section 20/धारा 20
- d) Section 22/धारा 22